उन्होंने यह समझा कि एक तरफ मुझे एलान करने के लिए कहा गया और दूसरी तरफ इलेक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं। यह समझकर उन्होंने यह कहा कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं त्यागपत्र देना चाहता हूं। दूसरी बात माननीय सदस्य ने जो पूछी है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग अनविलिंग हैं, उनको पंजाब में भेजने का कोई सवाल हीं पैदा नहीं होता है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे लोग वहां पर भेजे जाएं जो अपने एक्सपीरिएंस से पंजाब के हालात को दुरुस्त करने के लिए तैयार हों। अन-विलिंग होते हुए जबर्दस्ती किसी को भेजने का सवाल ठीक नहीं है और यह भी ठीक है कि जो सारी चीज अखबार में आती है, वह हंड्रेड परसेंट ठीक होती है। यह समझकर आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अन-विलिंग आदमी को वहां पर भेजने की कोशिश की जा रही है।

National Highways in Bihar

*143. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Highways in Bihar are in poor conditions; and

(b) if so, what amount has been sanctioned by Government for repair and maintenance of National Highways in Bihar?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) National Highways in Bihar are generally in traffic worthy condition, except few short stretches on various Highways. which occasionally get damaged by floods and rains.

During 1990-91 Rs. 1148.83 lakhs was allotted in respect of maintenance and repair works in Bihar. In 1991-92, Rs. 183.00 lakhs have been released so far. The total amount for the maintenance of the National Highway net work will be known after the Budget is presented and out of this, the allocation for Bihar will be determined.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मंत्री जी का जो लिखित जवाब है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ छोटे खडों को छोड़कर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग आमतौर पर यातायात के योग्य है, उन खंडों को छोड़कर जो बाढ तथा बारिश से कमी-कभार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि मंत्री जी कम से कम अपनी मारूति कार से दुर्गावती से आसनसोल तक और मोहनिया से आरा तक एक बार यात्रा कर लें, जो कि बाढ़ का इलाका नहीं है, बाढ से क्षतिग्रस्त रोड़ नहीं है बल्कि उस इलाके में तो कभी बाढ आती ही नहीं। इन रोडों की हालत जरा आप देख लें ... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : भ्रष्टाचार की बाढ भी तो आती है।

श्री राम अवधेश सिंह : हां, असल बात तो यह छिप गए कि भ्रष्टाचार की बाढ़ से यह रोड क्षतिग्रस्त है यह जरूर, पानी की बाढ़ से तो क्षतिग्रस्त नहीं है। तो इन दोनों रोड़ पर मैं आमंत्रित करता हूं मंत्री महोदय को, कि जरा अपनी मारूति कार से चलकर देख लें कि यह रोड यातायात के योग्य है या नहीं ? फिर लौटकर नहीं आ सकती आपकी मारूति कार उधर से। यह बात ठीक है उत्तर प्रदेश की सीमा तक राष्ट्रीय पथ ठीक है, उधर बंगाल में भी ठीक है, लेकिन बिहार का जितना इलाका है उसमें जी. टी. रोड़, जो सबसे प्रमुख रोड़ है, जैसा आप जानते हैं दिल्ली से, पूरे उत्तर भारत से कलकत्ता तक जोड़ने वाली यह सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड़, उसकी हालत इतनी खराब है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मान्यवर, आपको तो मैं नहीं कह सकता कि आप उधर चलिए, देखिए, लेकिन मंत्री जी को मैं जरूर कह सकता हूं।

श्री सभापति : तो क्या आप वहां मारूति कार का दौरा करेंगे ? यह प्रश्न है।

श्री अश्विनी कुमार : हम लोग भी साथ चलेंगे। मंत्री महोदय आप एक बार चलें। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी मारूति कार में या आपकी मारूति कार में ?

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान की सच्चाई की जांच करने के लिए उस इलाके का एक बार अपनी मारूति कार से दौरा करेंगे ?

श्री सभापति : अपनी कार भी इम्पोर्टेन्ट है। आपकी मारूति होनी चाहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : अपनी मारूति हो या जो भी कार हो।

श्री जगदीश टाइटलर : सर, पहले तो मैं ...(व्यवधान)...

श्री राम अवधेश सिंह : मेरा क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए।

श्री सभापति : आपका क्वेश्चन हो गया कि मंत्री जी अपनी मारूति में दौरा करेंगे क्या ?

श्री राम अवधेश सिंह : सर, पार्ट "बी", बिहार में कितना किलोमीटर जी. टी. रोड़ है और कितना किलोमीटर अन्य दूसरे राष्ट्रीय पथ हैं ? पार्ट "सी", मेंटीनेन्स और रिपेयर के लिए औसत प्रति किलामीटर कितने रुपए का प्रावधान है ? जी. टी. जैसे हैवी ट्रेफिक वाले राष्ट्रीय पथ पर चूंकि घिसाई ज्यादा होती है तो इसके लिए क्या कुछ अधिक रुपए का प्रावधान है? पार्ट "डी", ...

श्री सभापति : एक सप्लीमेंटरी में चार-चार पांच-पांच सवाल थोडे ही होते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : ठीक है, सर। तो दूसर क्वेश्चन में मैं पूछ लूंगा।

श्री जगदेश टाइटलर : सर, पहले तो मैं माननीय मेम्बर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वह नेशनल हाइवे है तो मैं जरूर आपके साथ जाना चाहूंगा। मगर, एक बात और भी कहना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच सालों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट सड़क बनाने के लिए पैसा दे रही है, बिहार सरकार उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करती। अभी पिछली दफा भी हमने जो बजट सेक्शन करके 1200 लाख रुपया भेजा था, उसमें सिर्फ 699 लाख रुपया उन्होंने इस्तेमाल किया और बाकी वापस भेज दिया। ...(व्यवधान).

श्री अश्विनी कुमार : खैरियत है, वापस भेज दिया।

श्री जगदीश टाइटलर : सुनिए, तो साहब। यहां पर मेरे पास पिछले ट्रांसपोर्ट मंत्री की एक बहुत सख्त चिट्ठी है .... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप तो बिहार के लोगों के बारे में गलतफहमी न रखिए। बहुत ईमानदार हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : पिछले हमारे सरफैस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी बड़ी सख्त चिटठी वहां के मिनिस्टर साहब को लिखी कि आप यह क्या कर रहे हैं, इतना पैसा हम दे चुके हैं और आप पैसा इस्तेमाल नहीं करते, आप एस्टीमेट्स देते नहीं, सड़क के बुरे हाल हैं, शायद वे मंत्री जी उसी सड़क पर गए होंगे अपनी मारूति पर। तो उन्होंने कहा कि जब पैसा दिया जाता है तो क्यों नहीं इस्तेमाल होता ? ऐसा लगता है कि वहां की सरकार बिल्कुल चाहती ही नहीं कि उन सड़कों की मरम्मत करे। मैं चाहूंगा कि जो पैसा हम इस बार भी देना चाहते हैं उस पैसे का पूरा इस्तेमाल हो, उन सड़कों की मरम्मत हो ताकि फिर आपकी तरफ से शिकायत न हो।

श्री राम अवधेश सिंह : यह तो मंत्री जी ने कहा कि जो रुपए हमने दिए उनका पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, यह तो इनका रिकार्ड है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो खर्च हुआ, यह क्या सही मायने में खर्च हुआ या नहीं या चीफ इंजीनियर या सुपरीडेंट इंजीनियर या कांट्रेक्टर की पाकेट में मिले-जुले ढंग से राशि चली गई ? अगर

वह चली गई तो क्या उसकी जांच के लिए भारत सरकार सी. बी. आई. डिप्यूट करेगी और पार्ट "बी" . . .

श्री सभापति : आभी पांच पहले हो चुके हैं, जरा ध्यान रखिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : जब सी.पी. डब्ल्यू. डी. महकमा है जो केन्द्रीय सरकार के भवनों के निर्माण वगैरह के लिए काम करता है और आप जो पैसा देते हैं उसका दुरुपयोग हो जाता है राज्य सरकारों द्वारा, तो क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार अपनी देख-रेख में अपनी एजेंसी के जरिए राष्ट्रीय मार्गों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था करती ? क्या सरकार ऐसा सोचती है कि राष्ट्रीय उच्च पथों के रख-रखाव के लिए कोई केन्द्रीय एजेंसी या सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ही प्रभारी बना दे ?

श्री जगदीश टाइटलर : सर, मैं तो बिहार की सरकार के ऊपर इतना इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर जो पैसा भी इस्तेमाल होता है, वह बिहार सरकार ही इस्तेमाल करती है । तो इल्जाम जो भ्रष्टाचार का लालू प्रसाद की गवर्नमेंट पर लग रहा है, मैं नहीं लगा रहा, आप लगा रहे हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : लालू और नो लालू । लालू प्रसाद नहीं, मैं बिहार सरकार कह रहा हूं । कोई सरकार हो । आज लालू की सरकार है, पीछे आपकी सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी ।

श्री सभापति : लालू प्रसाद माने बिहार सरकार ।

श्री राम अवधेश सिंह : मेरा मतलब है कि बिहार सरकार के अफसर और ठेकेदार भ्रष्टाचार की बाढ़ लाकर जो सड़क की तहस-नहस कर देते हैं, क्या भारत सरकार उसकी जांच कराएगी ?

श्री सभापति : इनका प्रश्न है कि क्या आप इसको करेंगे ?

श्री जगदीश टाइटलर : जो हमारे हिसाब से पैसा भेजा जाता है बिहार सरकार को, हम समझते हैं वह पैसे का ठीक इस्तेमाल करते हैं । अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, मुझे लिख दें, मैं उसकी इन्क्वायरी कराने की कोशिश करूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Will you take up the matter ?

SHRI JAGDISH TYTLER: It is a State subject. We will have to take up the matter with the State.

श्री राम अवधेश सिंह : पार्ट "बी" का जवाब नहीं दिया ।

श्री सभापति : उन्होंने दे दिया है ।

श्री राम अवधेश सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं अपनी देख-रेख में कोई एजेंसी बहाल करना चाहती है, जबकि सी.पी.डब्ल्यू. डी. जैसी आर्गेनाइजेशन इनके हाथ में है ?

श्री सभापति : आप ही का सवाल मैंने पूछ लिया था, इन्होने जवाब भी दे दिया, कि नहीं ।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने बड़ी सावधानी पूर्वक जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब न देने का तय कर लिया है । क्या वह शीघ्रातिशीघ्र वहां की इन्स्पेक्शन करने के लिए तैयार हैं, चलने का कार्यक्रम बनाएंगे क्या ?

श्रीमती रेणुका चौधरी : मगर आपको मंत्री जी को पहले मारुति कार दिलवानी पड़ेगी ।

श्री अश्विनी कुमार : वह तो मिल जाएगी मंत्री जी चलें तो सही । मैं सिर्फ मारुति पर ही नहीं कह रहा हूं, वह चाहे जिस गाड़ी पर चलें ।

श्री प्रमोद महाजन : मारुति तो किसी भी रास्ते पर गड़बड़ करेगी ।

श्री अश्विनी कुमार : मेरा इतना ही निवेदन है कि वह चलने का कार्यक्रम बनाएं

क्योंकि बहुत बार मंत्रियों के आने से सड़कों का रख रखाव अच्छा हो जाता है। हम दूसरों के दोष नहीं निकालना चाहते, परन्तु हमने देखा है कि रखरखाव अच्छा हो जाता है।

श्री सभापति : वह नहीं कि इन्हीं की कार होनी चाहिये। राम अवधेश जी कह रहे थे कि अपनी कार होनी चाहिये।

श्री अश्विनी कुमार : किसी कार से चलें, कार नहीं तो वह बस से चलें।

श्री राम अवधेश सिंह : एक बार वहां चलने का कष्ट करें। बिहार का भ्रमण भी हो जायेगा और केन्द्रीय मंत्री हैं तो बिहार का एक अनुभव भी हो जायेगा।

श्री सभापति : अब आप आगे पूछो।

श्री अश्विनी कुमार : एक तो इसमें उनका स्पष्टीकरण चाहूंगा। दूसरे, यह कि नेशनल हाईवे जिसकी हमारे माननीय मित्र ने पहले चर्चा की कि दुर्गावती से आसनसोल तक का हिस्सा है उसमें कितने स्ट्रेचिज हैं मंत्री महोदय की जानकारी के हिसाब से जो कि खराब हैं ? कितने पुल हैं जो आज तक सन 47 के बाद से चौड़े नहीं हुये हैं ? कितना एरिया है जहां पर चौड़ीकरण—वाइडनिंग आफ रोड्स का हुआ है ? कितने माइल्स ऐसा है जो आज तक वाइडनिंग नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत बार ट्रेवल किया है। कुछ-कुछ पोर्शन वाइडनिंग हुए हैं और कुछ-कुछ नहीं हुये हैं तो पूरी लम्बाई में से कितने पोर्शन्स हैं जिनका पूरा वाइडनिंग हो गया है ? कितने पुल्स थे जिनका नवीकरण हो गया है और चौड़ाकरण हो गया है और कितने हैं जो आज तक नहीं हुये हैं और जो रुपया आप आबंटित कर रहे हैं उसके हिसाब से कब तक वह हो सकता है और क्या वह सड़क जो स्पीड मंत्री महोदय तय करें, उस स्पीड पर गाड़ियों के चलने लायक कब तक यह तय करा सकते हैं ? स्पीड भी इनकी, रुपये भी इनका सारी सुविधायें हम इनको दे रहे हैं। हम एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, कुछ आश्वासन चाहते हैं। राम अवधेश जी का उत्तर नहीं दिया कि अगर बिहार सरकार काम को करने में असमर्थ है तो क्या इसके अंदर परिवर्तन करके केन्द्र सरकार जिम्मेदारी लेने का प्रयास करेगी या निश्चय करेगी ?

श्री जगदीश टाइटलर : पहले, तो हम जरूर जानना चाहेंगे, आप के साथ ही जाना चाहेंगे पार्लियामेंट के बाद, जब आप फैसल कर लेंगे। दूसरे, जब भी स्टेट सरकारों से पैसे की डिमांड आयी उतने पैसे की मांग हमने प्लानिंग कमीशन में की, फाइनेंस मिनस्ट्री में की। उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका, उतना पैसा नहीं मिला। जितना पैसा हमें मिलता है उसके हिसाब से हम रिपेयर्स भी करते हैं, वाइडनिंग भी करते हैं, ब्रिजेज की भी रिपेयर करते हैं। तो बैकलौग जो 1-4-85 से है वह तकरीबन 8426 किलोमीटर है और इसके लिये हमें 86 करोड़ 20 लाख रुपये की जरूरत थी और आज बैकलौग क्योंकि सरकार से पैसा नहीं मिला, चार सौ करोड़ की बैकलौग है, तो मेरा जो प्रोग्राम जो आपके सवाल का है, वह मैं तभी दे सकता हूं जब मुझे पता चलेगा कि बजट में कितना पैसा मिलता है, उस हिसाब से उस पैसे को मैं बिहार में इस्तेमाल करूंगा।

श्री अश्विनी कुमार : सभापति महोदय, जो मेरे प्रश्न थे उनको मंत्री महोदय ने.... (व्यवधान)

श्री सभापति : वह डिटेल्स में चाहते हैं कि कहां-कहां वाइडनिंग आफ रोड्स है, वह आप बता दीजिए। दुर्गावती से आसनसोल तक कितना वाइडनिंग है, कितना नहीं ? कितने पुल हुये कितने नहीं ?

श्री जगदीश टाइटलर : मैं बिहार की बात कर रहा हूं। मुझे जैसा पैसा सेक्शन होगा उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा।

श्री अश्विनी कुमार : कितने पुल वाइंडन हुये हैं, जरा खबर तो कर दीजिए कि 42 साल में इतने पुल आज तक वाइडनिंग नहीं हुये हैं, वहीं 8 फुट वाले चल रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN: He will place the details on the Table of the House.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Chairman, Sir, the point is, road is a basic infrastructure for anything. The condition of the roads, particularly, the State roads, and also the National Highways, in Bihar, is deplorable. In fact, this is an understatement. As a result of the calculated neglect by the Central Government, or because of inefficiency or diversion of funds by the State Government, regardless of political persuasion, the people of Bihar are suffering. The kind of answer that the hon. Minister has given does not provide any guarantee that the people of Bihar are going to get any relief. I think, some emergency measures, some extraordinary measures, are required, in order to improve the quality of the roads. This is one thing.

Secondly, the per capita share of Bihar, as regards National Highways, is again an index of the neglect of Bihar. The people of Bihar are suffering. But ultimately, the country will have to pay for it. I hope the hon. Minister is aware, his colleagues are aware, of the consequences of this neglect. Will the hon. Minister react on this, rather than saying that the State Government is responsible? Ultimately, it is the country which is going to suffer. Therefore, he should not look at it from the point of view of Central-State subjects or of political parties. I would like the hon. Minister to own up the responsibility that he will try his best that the quality of roads would improve in Bihar within a time-bound programme.

SHRI JAGDISH TYTLER: I would like to inform the hon. Minister that the amount of money which the Centre is sanctioning, they are not spending that. You must see today that the money which we send, that money should, at least, be spent so that some percentage of roads are repaired. I would like to inform the Members how much has been sanctioned by the Central and how much has been spent by them in the last five years. On an all-India basis in 1986-87 Rs. 9325 lakhs were sanctioned, out of which Rs. [illegible] lakhs were sanctioned for Bihar, practically 10 per cent of the total amount of money which was given to all the States. In 1990-91 I will give you the figure. Rs. 15312 lakhs was the total sanction for the country. Bihar got Rs. 114.38 lakhs. Out of this only an amount of Rs. 906 has been spent. I have got the figures from 1990 to 1991. Every year the money has been spent on the roads and this is the money which we have given to Bihar. At least you see that the State Government utilises this money so that the roads will be repaired.

MR. CHAIRMAN: Shri Chaturanan Mishra.

श्री राम अवधेश सिंह : इसलिए तो पूछा कि आपकी कोई सेंट्रल एजेंसी है या नहीं... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have called Shri Chaturanan Mishra.

आप तशरीफ रखिए ।

श्री चतुरानन मिश्र सभापति महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो रोड के मद में रुपए सेंक्शन हुए हैं वह एक ही साल में हुए हैं या कई वर्षों में हुए हैं ? अगर कई वर्षों में हुए हैं तो क्या आप पिछले 4-5 वर्षों की फिगर्स देंगे कि कब-कब कितना-कितना रुपया सेक्शन हुआ है ?

महोदय, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या मंत्री महोदय बिहार जाकर वहां के लोक निर्माण विभाग के मंत्री के साथ बैठकर इस संबंध में विचार करेंगे, जिसमें हम लोग भी शामिल हों और कोई ऐसी कार्यबद्ध योजना बनाई जाए जिससे जो बहुत ही डैमेज्ड रोड्स हैं उसको प्रॉयोरिटी देकर हम लोग ठीक करवाने का कार्यक्रम करवा सकें ।

SHRI JAGDISH TYTLER: I would request the Bihar Transport Minister to come to Delhi during the Parliament session. I will call you and discuss the problem. Otherwise, after the Parliament session I am prepared to go to Patna.

SHRI CHATURANAN MISHRA: After Parliament session?

SHRI JAGDISH TYTLER: If you want earlier, I could do it.

श्री सभापति: आप बता दीजिए कि कब कितना पैसा सैंक्शन हुआ है।

SHRI JAGDISH TYTLER: In 1987-88 the total amount sanctioned was Rs. 1350 lakhs out of, which only Rs. 1272 lakhs were spent. In 1988-89 Rs. 1200 lakhs were sanctioned and the amount spent was Rs. 1025.97 lakhs only. In 1989-90 an amount of Rs. 1200 lakhs was sanctioned and they spent only Rs. 699.03. In 1990-91 Rs. 11 lakhs were sanctioned, upto February 1991 an amount of Rs. 906 61 lakhs has been spent.

MR. CHAIRMAN: Next Question No. 145.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: What about Question No. 144?

MR. CHAIRMAN: It has been transferred to 30th July.

*144. [*Transferred to 30th July,* 1991]

चकमा शरणार्थी

***145. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा † डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के शिविरों में लगभग 56,000 चकमा शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये लोग देश में कब से रह रहे हैं;

(ग) क्या इन शरणार्थियों के आवास तथा भोजन आदि का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो जून, 1991 तक इन शरणार्थियों के भोजन, आवास तथा अन्य प्रबन्धों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) 53,275 refugees including Chakmas are living in refugee camps in Tripura.

(b) The present influx of tribal refugees including Chakmas from Bangladesh has started in April, 1986.

(c) Yes, Sir.

(d) Grant-in-aid amounting to Rs. 2951.267 lakhs been released to the Government of Tripura till June, 1991 for meeting the expenditure on the maintenance of these refugees.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, actually it is not the question of money that you have spent. The question is that Chakmas have been living in Tripura for a number of years. You can call some of them inhabitants. Children have been born there. There are no arrangements for their education. Their living conditions are deplorable. Do you consider that these people can be sent back and that this is their temporary residence only, or do you feel that they will continue to live in Tripura and, if so, are you planning any permanent arrangement for them?

SHRI M. M. JACOB: Sir, it is true, as the honourable Member has said, that some of the Chakma refugees have been living there for almost five years now. We are making all attempts to see that these refugees go back to the samt place from where most of them come, that is. Bangladesh. We had actually met several times

†The question was actually asked on the floor of the House by Sardar Jagjit Singh Aurora.